The Pioneer (Hindi)

Global standard warning label will boost food export

पैकेज्ड फूड के एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत में विज्ञान आधारित फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योग के मुख्य प्रतिनिधियों और फूड निर्माताओं ने बताया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधि एफओपीएल से पैकेज्ड फूड उत्पादों, खासकर जो फूड एमएसएमई यूनिटों द्वारा बनाया जाता है, उसे दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट किए जाने को काफी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड एवं बेवरेज के लिए वृद्धि की दर सर्वाधिक है। यह फूड सामग्री अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होने के अलावा इसमें काफी ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर, साल्ट एवं एडिटिव्स होते हैं। 2006 से 2019 के बीच यूरोमॉनिटर सेल्स डेटा के मुताबिक पैकेज्ड जंक फूड एवं सॉफ्ट ड्रिंक्स का रिटेल मूल्य भारत में 13 सालों में 42 गुना बढ़ गया। फूड प्रोसेसिंग उद्योग, जिसे भारत सरकार रोजगार निर्माण के लिए मुख्य सेक्टर मानती है, मौजूदा समय में 200 बिलियन डॉलर का है, जो बढ़कर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के 32 प्रतिशत फूड बाजार में 'प्रोसेसिंग उद्योग' का वर्चस्व है, इसलिए स्वादिष्ट एवं लोकप्रिय देसी स्नैक और कन्फेक्शनरी बनाने वाला विशाल एमएसएमई सेक्टर इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशिम सान्याल, सीओओ, कंज्यूमर वॉइस एवं सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, एफएसएसएआई के तात्कालीन सदस्य ने कहा, यह देखकर खुशी होती है कि फूड इंडस्ट्री, जो मुख्य अंशधारक है, यह इस लेबल को अपनाने के लिए तैयार है, जो देश के लिए सबसे अच्छा है। एमएसएमई सेक्टर की इस क्षमता को समझते हुए सरकार प्रोसेसिंग उद्योग के लिए फूड पार्क को बढ़ावा दे रही है और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तत्पर है। 10,900 करोड़ रु. की वित्तीय परिव्यय लागत से बनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज (पीएलआईएसएफपीआई) भारत में विश्व स्तर की फूड मैनुफैक्चरिंग कंपनियों को प्रोत्साहित करती है और भारतीय फूड ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करने में सहयोग करती है।

भारत में आहार से संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज, मोटापा आदि व्यस्कों में ही नहीं, अपितु बच्चों में भी चौंकानेवाली दर से बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी भारतीय उपभोक्ता साल 2030 तक प्रोसेस्ड एवं ब्रांडेड फूड उत्पादों पर 6 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे। उपभोक्ताओं की आहार की पसंद एवं खरीद के निर्णय पर हावी होते अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के साथ फूड उद्योग को यह समझ में आ रहा है कि फूड पैकेट पर आसानी से समझ आने वाली चेतावनी इस मामले में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज देश में जब आजादी का अमृत महोत्सव - स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव मनाया जा रहा है, तो खाने की सुरक्षा, पोषण और देश का स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं।

छह राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, असम, और पश्चिम बंगाल से फूड कंपनियों और औद्योगिक संगठनों की यह सभा उस समय आयोजित की गई है, जब देश में एपेक्स फूड रैगुलेटर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) भारत के लिए बहुप्रतीक्षित एफओपीएल रैगुलेशन के बारे में विचार-विमर्श कर रहा है। जहां एफएसएसएआई ने 'हैल्थ स्टार्स रेटिंग' के लिए अपनी रुचि प्रदर्शित की है, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहक भ्रमित होंगे, डॉक्टरों एवं वैज्ञानिक समुदायों का मानना है कि भारत को चेतावनी लेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इस लेबल से न केवल फूड आइटम खाने से होने वाली बीमारी का पता चलता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि तेजी से बढ़ता हुआ फूड मार्केट एक सेहतमंद भविष्य के लिए तैयार है।

गुरजीत सिंह कंवोज, डायरेक्टर, पाम्को फूड प्राईवेट लिमिटेड, पंजाब ने कहा, हम अपनी विटिम लाईन को इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं ताकि ग्राहकों के स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर न हो। हमारे जैसे उद्योग ग्राहकों के लिए हितकर लेबल अपनाने के इच्छुक हैं, ताकि परिवार सेहतमंद विकल्प चुन सकें और हमारे उद्योग में फायदा व नौकरियां बढ़ें।